

# उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों में 5738 पीएम ई बसों को दी गई मंजूरी

**मनोधि लिवारी नई दिल्ली :** पीएम ई बस सेवा के तहत सौ से अधिक शहरों में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन इसी साल के शुरुआती महीने में आरंभ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 77 शहरों की ओर से मिले प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इन शहरों की ओर से अब तक 5738 बसों के प्रस्ताव मिले हैं। अधिकांश में टेंडर जारी कर दिए गए हैं।

केंद्रीय शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने दैनिक जागरण को बताया कि पीएम ई बस सेवा के जरिये केंद्र सरकार शहरी क्षेत्रों में परिवहन के द्वारों को नए दीर में ले जाना चाहती है। इस योजना के तहत 10 हजार इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती के लिए 20 हजार करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता दी जाएगी। योजना मार्च 2037 तक चलेगी।

साहू के अनुसार यह योजना इसलिए शहरी सुधार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके



- इसी साल के शुरुआती महीनों में आरम्भ हो जाएगा संचालन : तोखन साहू
- केंद्र सरकार की सहायता से शहरों में चलनी हैं 10 हजार इलेक्ट्रिक बसें

तहत पात्र शहरों में बस डिपो और चारिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास और आधुनिकीकरण के लिए भी सहायता दी जाएगी। पीएम ई बसों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए अब तक 66 शहरों में बिहाइड फ्रीटर पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर और सिलिंग डिपो इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 884 करोड़ रुपये की मंजूरी दी जा चुकी है, जिसमें 438 करोड़ रुपये राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश को

जारी भी कर दिए गए हैं।

जिन राज्यों के शहरों के लिए ई बसों को मंजूरी दी गई है, उनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, असम शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, कोरबा, रायपुर, बिहार में गया, पूर्णिया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, राजस्थान में अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, मध्य प्रदेश में इटीर, महाराष्ट्र में उल्लासनगर, अकोला और कोल्हापुर, ओडिशा में राऊरकेला, गुजरात में भावनगर, गांधीनगर, जामनगर, राजकोट और वडोदरा, मध्य प्रदेश में भोपाल और उज्जैन में बस डिपो और चारिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है।

साहू ने बताया कि इस योजना के दूसरे चरण में ग्रीन अर्द्धन मोबिलिटी परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता देने का निर्णय किया गया है। ये बस सेवाओं के लिए पुरक योजना साधित होगी।